



परिवहन अवसंरचना का संरक्षण और विकास

परिवहन अवसंरचना का संरक्षण और विकास

1. कोयला संरक्षण

कोयले का संरक्षण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, विशेषकर तब जब कि कोयला भण्डार सीमित हैं। कोयला संरक्षण के पहलू पर आयोजना के स्तर से ही ध्यान दिया जाता है तथा कार्यान्वयन चरण में अधिकतम प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। कोयला सीमों के लिए खानों का डिजाइन तकनीकी व्यवहार्यता तथा आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए ओपनकास्ट अथवा भूमिगत पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है।

वर्तमान में मशीनीकृत ओपनकास्ट (ओसी) खनन उथली गहराई में थिक सीमों के निष्कर्षण के लिए आम तौर पर अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी है। यह संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से प्राप्ति का प्रतिशत लगभग 80% से 90% है। वर्तमान में, कोयला उद्योग में इस प्रौद्योगिकी की प्रबलता है और इसके माध्यम से देश के कोयला उत्पादन में 94% से ज्यादा का योगदान मिलता है। इसके अलावा, जब भी व्यवहार्य हो, भूमिगत खानों के विकसित पिलर्स का निष्कर्षण ओपनकास्ट प्रचालनों के माध्यम से किया जा रहा है।

लांगवाल पद्धति, शार्टवाल पद्धति, हाईवाल माइनिंग जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों तथा सतत खनन प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप भूमिगत खनन (यूजी) में निष्कर्षण के प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

रेजिन कैप्सूल वाली मशीनीकृत बोर्लिंग से रूफ सपोर्ट प्रौद्योगिकी में सुधार के परिणामस्वरूप वाइडर गैलरी स्पैन को बनाए रखना और रूफ की खराब दशाओं के अंतर्गत अधिक कारगर ढंग से सीमों का निष्कर्षण संभव हो पाया है जिसके परिणामस्वरूप कोयला संरक्षण में सुधार हुआ है।

2. रेत भराई

भूमिगत खानों में रेत भराई अभी भी कोयला संरक्षण का एक कारगर साधन है जिसका महत्वपूर्ण सतही संरचना, रेलवे

लाइनों, नदियों, नालों आदि जैसे बिल्ट-अप क्षेत्रों के नीचे मौजूद भूमिगत कोयला सीमों से कोयला पिलर्स के निष्कर्षण हेतु व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है अन्यथा इसके परिणामस्वरूप पिलर्स में कोयला अवरुद्ध हो सकता है। रेत भराई से विभिन्न उठानों में थिक सीमों के निष्कर्षण में भी सहायता मिलती है जिससे निष्कर्षण का प्रतिशत बढ़ा है। रेत की कमी के कारण, रेत के विकल्प के रूप में भूमिगत खानों में रेत भराई के लिए फ्लाइ ऐश, बॉइल, ऐश, क्रशड ओवरबर्डन पदार्थ आदि जैसे अन्य पदार्थों के उपयोग हेतु विभिन्न प्रायोगिक परीक्षण किए जा रहे हैं। वर्तमान में, भूमिगत कोयला खानों में रेत भराई के लिए वाणिज्यिक रूप से क्रशड ओवरबर्डन पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है, इसका उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां खान के आस पास रेत उपलब्ध न हो या सुदूर नदी स्रोतों से रेत की ढुलाई महंगी पड़ती हो।

3. परिवहन अवसंरचना का संरक्षण और विकास

कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत गठित कोयला संरक्षण एवं विकास सलाहकार समिति (सीसीडीएसी) के लिए कोयला नियंत्रक सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है। कोयला नियंत्रक का कार्यालय कोलफील्ड्स क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी कार्य, वैज्ञानिक विकास कार्य, सड़क और रेल अवसंरचना परियोजनाओं के संबंध में सीसीडीएसी के माध्यम से निधियां जारी करने हेतु कोयला कंपनियों से आवेदनों/दावों से संबंधित प्रस्तावों को प्राप्त करता है और इनकी जांच करता है।

वर्ष 2021-22 की दो प्लान स्कीमों के लिए बजट निम्नानुसार है:-

- कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा – 6 करोड़ रु.
- कोलफील्ड्स में परिवहन अवसंरचना का विकास – 65.48 करोड़ रु.

वर्ष 2020-21 से संरक्षण एवं सुरक्षा शीर्ष में 3.227 करोड़ रु. तथा परिवहन अवसंरचना विकास शीर्ष में 93.31 करोड़ रु. की स्पिलओवर राशि थी।

85वीं सीसीडीए समिति ने संरक्षण एवं सुरक्षा शीर्ष में 8.05 करोड़ रु. तथा परिवहन अवसंरचना विकास शीर्ष में 0.405 करोड़ रु. की अनुमोदित की है।

कोयला मंत्रालय ने संरक्षण एवं सुरक्षा शीर्ष में 1.01 करोड़ रु. तथा परिवहन अवसंरचना विकास शीर्ष में 11.06 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

सीसीडीएसी की आयोजित बैठकों की संख्या:

उप-समिति: (22.03.2021)

मुख्य समिति दिनांक: 1 (दिनांक 16.09.2021 को)

दिसंबर, 2021 तक की स्थिति (85वीं सीसीडीए समिति के अनुमोदन अनुसार और कोयला मंत्रालय द्वारा जारी निधि):-

शुरू किए गए बचाव कार्य: 5

शुरू किए गए वैज्ञानिक विकास कार्य: 4

आंशिक रूप से वित्तपोषित सड़क परियोजनाओं की लंबाई: शून्य

आंशिक रूप से वित्तपोषित रेल परियोजनाओं की लंबाई: 1.60 कि.मी.

4. सीआईएल: रेल अवसंरचना परियोजनाएं

भविष्य में उत्पादन तथा निकासी में योजनाबद्ध वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से सीआईएल ने मुख्य रेल अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण का कार्य आरंभ किया है। इन रेल अवसंरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन भारतीय रेलवे (डिपॉजिट आधार पर) अथवा रेलवे, सहायक कंपनी (सीआईएल का प्रतिनिधित्व करने वाली) तथा संबंधित राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले आईआरसीओएन के साथ, संयुक्त उद्यम कंपनियों के जरिए किया जा रहा है।

तीन (03) प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाएं डिपॉजिट आधार पर और चार (04) रेल अवसंरचना परियोजनाएं संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

4.1 डिपॉजिट आधार:

ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पटना द्वारा झारखंड में सीसीएल के नार्थ करनपुरा क्षेत्र के लिए 3587.37 करोड़ रु. की परियोजना लागत से लगभग 44.37 कि.मी. लम्बाई वाली तोरी-शिवपुर न्यू बीजी लाइन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पूरी लाइन के दोहरीकरण का कार्य दिसंबर, 19 में शुरू हो गया था। इस रेल लाइन की ट्रिपलिंग को 32 एमटीपीए से बढ़ाकर 100 एमटीपीए तक करने का कार्य किया जा रहा है।

साउथ ईस्टर्न रेलवे, कोलकाता द्वारा महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित आईबी वैली कोलफील्ड्स के लिए 1123.90 करोड़ रु. की लागत से लगभग 52.41 कि.मी. की लंबाई वाली झरसुगुडा- बारापल्ली- सरडेगा रेलवे अवसंरचना परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है और ये लाइन अप्रैल- 2018 में प्रारंभ हो चुकी है। बारापल्ली में लोडिंग बल्बों के साथ इस रेल मार्ग के दोहरीकरण तथा रेल फ्लाईओवर कॉम्प्लेक्स सहित झारसुगुडा यार्ड की रि-मॉडलिंग को अनुमोदन दे दिया गया है और इनका क्रियान्वयन 3200 करोड़ रुपए की अनुमानित पूंजी से किया जा रहा है। इससे रेलवे लाइन की उत्खनन क्षमता 32 एमटीपीए से बढ़ाकर 65 एमटीपीए हो जाएगी।

4.2 संयुक्त उद्यम आधार:

49.085 किमी लंबाई वाले शिवपुर-कठौतिया खंड का कार्यान्वयन सीसीएल, आईआरसीओएन तथा इसके साझेदार के रूप में झारखंड सरकार के साथ झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) नामक जेवी कंपनी द्वारा 1799.64 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और इस परियोजना की वित्तीय समापन प्रक्रियाधीन है।

ईस्ट रेल कोरिडोर का कार्यान्वयन एसईसीएलए आईआरसीओएन तथा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एक जेवी कंपनी छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लि. (सीईआरएल) द्वारा दो चरणों में किया जा रहा है:

चरण-I: 3055 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से गारे-पाल्मा तक स्पर के साथ खर्सिया-धर्मजयगढ़ और लगभग 132 कि. मी. की तीन फीडर लाइन। खर्सिया से धर्मगढ़ तक 74 कि.मी

लंबे मुख्य रेल कॉरीडोर का निर्माण दिनांक 26 जुलाई, 21 को पूरा हो गया है। इस समय इस नई बीजी रेलवे लाइन के माध्यम से कोयला उत्तखनन का कार्य किया जा रहा है। 3 फीडर लाइनों और गारे-पाल्मा-घारघोंडा स्पर के पहले ब्लॉक खंड का निर्माण कार्य चल रहा है और इसके मार्च, 22 पूरा होने की संभावना है।

चरण-II: 1686.22 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से लगभग 62.5 कि.मी. लंबाई वाली धर्मजयगढ़-कोरबा रेल लाइन। वित्तीय समापन और भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।

एसईसीएल, आईआरसीओएन और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा गठित एक जेवी कंपनी **छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)**, वाया दिपका, कटघोड़ा, सिंदुरगढ़ और पासन ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरिडोर (जेवरा रोड से पेंड्रा) का निर्माण कर रही है। जिसकी लम्बाई 135 किलोमीटर है और जहां 4970.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर लगभग 35 किलोमीटर लंबी फीडर लाइनें हैं। रेल लाइनों के निर्माण के लिए सिविल निविदाओं को सौंपा गया और निर्माण कार्य चल रहा है।

एमसीएल, आईआरसीओएन और ओडिशा राज्य सरकार द्वारा गठित जेवी कंपनी **महानदी रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल)**, कोयले की निकासी को पूरा करने के लिए एमसीएल के तलचर कोलफील्डस में रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के निर्माण का कार्य कर रही हैं।

1700 करोड़ रुपये (भूमि की लागत को छोड़कर) की अनुमानित लागत से एमसीएल के तलचर कोलफील्डस में अंगुल-बलराम-झारपाडा-टेन्टुलोई में 69.10 कि.मी. लम्बा लिंक (जिसमें 14.22 कि.मी. लंबाई वाले झारपाडा-कलिंग-अंगुल की लिंक शामिल हैं)।

पहले चरण में, अंगुल-बलराम सेक्शन का निर्माण 145 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत से किया जा रहा है और इसके जून, 22 तक शुरू होने का अनुमान है। वित्तीय समापन अग्रिम चरण में है और इसके फरवरी, 22 तक पूरा होने की संभावना है। दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है।

4.3 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं

सीआईएल ने 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी' परियोजनाओं के तहत मशीनीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग प्रणाली को उन्नत करने के लिए कदम उठाए हैं। प्रथम चरण में, सीआईएल ने खानों में 4 एमटीवाई और इससे अधिक की क्षमता वाली 35 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं चिह्नित की हैं। इन परियोजनाओं से वर्ष 2023-24 तक इस समय 150 एमटीपीए से 565 एमटीपीए तक मशीनीकृत उत्तखनन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इन अवसंरचना परियोजनाओं से कोयला गुणवत्ता में सुधार होगा, अंडर-लोडिंग प्रभावों में बचत होगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

इन 35 एफएमसी परियोजनाओं में से, 70 एमटीपीए क्षमता वाली 5 परियोजनाएं शुरू हो गई हैं, 12 एमटीपीए क्षमता वाली 1 परियोजना पीजी टेस्ट रन के अधीन है और 295.5 एमटीपीए क्षमता वाली 26 परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और अनुसूचित हैं। इन शेष तीन एफएमसी परियोजनाओं में से, 5 एमटीपीए की 1 परियोजना की पुनः निविदा की गई जबकि 32 एमटीपीए की 2 एफएमसी परियोजनाओं की निर्माण साइटों को वन मंजूरी के कारण निष्पादन एजेंसियों को सौंपा नहीं जा सका।

सीआईएल ने सीएसआईआर-राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनईईआरआई) के लिए 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी' परियोजना के तहत लागू किए जाने वाले पर्यावरणीय, सामाजिक और संभावित आर्थिक लाभ के मुद्दों को कवर करते हुए कोयला लोडिंग एवं परिवहन गतिविधियों में मैकेनाइज्ड कन्वेयर बेल्ट और साइलो लोडिंग सिस्टम के लाभों की जांच के लिए एक अध्ययन प्रायोजित किया। अध्ययन का निष्कर्ष इस प्रकार है:-

एफएमसी से संबंधित अवसंरचना और गतिविधियों के चालू होने से वायु प्रदूषण में कमी, सीओ 2-कार्बन फुटप्रिंट में कमी और कुछ चुनिंदा रिसेप्टर बिंदुओं पर परिवेशी ध्वनि स्तरों (दिन या रात के समय के वार्षिक औसत स्तर) में कमी के रूप में पर्यावरणीय लाभ हुए हैं। कम टिपर माइलेज और पे लोडर ऑपरेशन के कारण डीजल की खपत में कमी आई। लिंगराज में डीजल के लिए लागत बचत 10.24-50.19 करोड़ रुपये

और गेवरा में 23.08 करोड़ रुपये है। एफएमसी ने उन फर्मों/एजेंसियों/संगठनों के लिए आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित किए हैं, जिन्होंने एफएमसी को चालू करने और उसके प्रचालन के लिए सामग्री, वित्तीय सुविधाएं और सेवाएं दी हैं और दे रहे हैं।

5. एससीसीएल द्वारा किए गए प्रयास –

5.1 रेत भराई:

सार्वजनिक भवन, कॉलोनियां, रेल लाइनें, सार्वजनिक सड़कें आदि जैसे महत्वपूर्ण सतही अवसंरचनाओं की सुरक्षा के लिए भूमिगत खाली स्थानों/गोफ (कोयला निकालने के बाद) को नदी की रेत से भर (भराई) दिया जाता है। रेत की अत्यधिक कमी के कारण, एससीसीएल खानों की भूमिगत खानों में भराई के लिए रेत के विकल्प के रूप में बॉटम ऐश, बॉयलर ऐश और क्रशड ओवर बर्डन जैसे अन्य पदार्थों के इस्तेमाल के विभिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं।

एससीसीएल की 14 भूमिगत खानों में नदी की रेत, बॉटम ऐश और प्रोसेस्ड ओवर बर्डन द्वारा भराई की जा रही है।

अप्रैल से दिसंबर, 2020 के दौरान भूमिगत खानों में इस्तेमाल किए गए 13.11 एलसीयूएम भराई पदार्थों में से 25.5% प्रोसेस्ड ओवरबर्डन, 42% बॉटम ऐश और 32.5% नदी की रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है।

गहरी ओपनकास्ट खान के अंतिम हाई वॉल में शेष कोयले को निकालने के लिए एससीसीएल की खान में हाईवॉल खनन का कार्य चल रहा है।

5.2 कोयला निष्कासन के लिए एससीसीएल रेल और अवसंरचना परियोजना

एससीसीएल ने 2024 तक कोयला उत्पादन और प्रेषण में 80 मि.ट. तक और 2029–30 तक 100 मि.ट. की नियोजित बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए, एससीसीएल द्वारा निष्कासन और अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं—

- कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी): 50 एमटी क्षमता के 9 सीएचपी के जरिए रेल/एमजीआर प्रणालियों द्वारा कोयला भेजा जाता है। शेष कोयले की सड़क द्वारा

दुलाई की जा रही है।

- 3.50 एमटीपीए वाली एसआरपी/ओसी/सीएचपी 13.01.2020 से प्रचालनरत। इसके लिए नवंबर, 2021 तक 227.60 करोड़ रु का व्यय हुआ।
- 10 एमटीपीए की क्षमता वाली जेवीआर ओसी सीएचपी का 80% कार्य पूरा हो चुका है और इसे जनवरी, 2021 तक शुरू किए जाने की संभावना है। इस सीएचपी से कनेक्टिड, बीडीसीआर से सद्दुपल्ली रेलवे लाइन के फरवरी, 2022 तक पूरे होने संभावना है। लगभग 75% कार्य पूरा हो गया है। रेलवे साइडिंग का 30% कार्य भी पूरा हो गया है। नवंबर, 2021 तक योजनागत 1301.73 करोड़ रु में से 1021.82 करोड़ रु वास्तविक व्यय है।
- 10 एमटीपीए वाली नैनी सीएचपी के 2023–24 में पूरा होने की संभावना है। यह योजना प्रारंभिक चरण में है।
- 10 एमटीपीए और 620 करोड़ रु के कैपेक्स वाली वीके ओसी सीएचपी परियोजना के 2024–25 तक पूरा होने की संभावना है।

रेलवे लाइन, रेलवे साइडिंग और कोल हैंडलिंग प्लांट बनाने के अलावा प्रि-वे वैगन लोडिंग सिस्टम, क्रशर, अप्रोच सड़क/बीटी सड़क/एस्फॉल्ट सड़क के संस्थापन की व्यवस्थाएं की जा रही हैं: कोयले की दुलाई के लिए आवश्यकतानुसार सड़कें बनाई जा रही हैं और इनका रख-रखाव किया जा रहा है।

6. एनएलसीआईएल द्वारा किए गए प्रयास:

6.1 तालाबीरा II एवं III ओसीपी (20 एमटीपीए):

क. एफएमसी उपलब्धि:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	शुरू करने की अनुमानित समय-सीमा
(i)	खनन परिचालनों की शुरूआत	2019.20
(ii)	सीएचपी, साइलो आधारित प्रेषण और मशीनीकृत कन्वेयर प्रणाली (एमडीओ का कार्यक्षेत्र)	अगस्त-2023
(iii)	रेलवे साइडिंग	अक्तूबर-2023

ख. खनन परिचालनों की शुरुआत:

तालाबीरा II एवं III ओसीपी में कोयला उत्पादन 26.04.2020 से आरंभ हुआ। 30.11.2021 तक संचयी कोयला उत्पादन 43.96 एल.टी. है।

ग. सीएचपी, मशीनीकृत कन्वेयर प्रणाली और रैपिड लोडिंग साइलो:

सीएचपी, मशीनीकृत कन्वेयर प्रणाली और रैपिड लोडिंग साइलो का निर्माण एमडीओ के कार्यक्षेत्र में आता है। एमडीओ द्वारा प्रस्तुत संशोधित डीपीआर के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्शत अनुमोदन दिया गया है। दिनांक 29.10.2021 को एमडीओ द्वारा एलओए जारी किया गया है। कार्य पूरा होने की समय-सीमा एलओए जारी होने की तारीख से 22 माह है।

घ. रेलवे साइडिंग (तालाबीर-II एवं III ओसीपी):

एनएलसीआईएल द्वारा 20 एमटीपीए वाली तालाबीर-II एवं III ओसीपी का विकास किया जा रहा है। खनन परिचालन 11.12.2019 से शुरू हो चुका है। कोयला उत्पादन 26.04.2020 से आरंभ हुआ था।

आरंभ में, कोयले की सड़क मार्ग से निकट के रेलवे साइडिंग तक ढुलाई की जाएगी ताकि इसकी आगे पारादीप बंदरगाह तक ढुलाई की जा सके और इससे

आगे एनटीपीएल, तुतीकोरिन तक प्रेषण किया जा सके। तालाबीर-II एवं III ओसीपी में निजी रेलवे साइडिंग बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। मशीनीकृत कन्वेयर प्रणाली से कोयले की पिट हेड कोयला स्टॉक यार्ड से रेलवे साइडिंग तक ढुलाई की जाएगी। कंप्यूटरीकृत रैपिड लोडिंग सिस्टम (साइलो) के जरिए रेलवे वैगनों में कोयला लोड किया जाएगा। रेलवे साइडिंग की शुरुआत होने के बाद सड़क ढुलाई से पूरी तरह बचते हुए मशीनीकृत कन्वेयर प्रणाली, रेल और समुद्र जैसे विभिन्न माध्यमों के जरिए पिट हेड कोयला स्टॉक यार्ड से एनटीपीएल, तुतीकोरिन, तमिलनाडु तक कोयले की ढुलाई की जाएगी। रैपिड लोडिंग साइलो प्रणाली का निर्माण एमडीओ के कार्यक्षेत्र में आता है।

रेलवे कॉरिडोर के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) का कार्य मैसर्स आरआईटीएस को सौंपा गया था। रेलवे साइडिंग के प्रचालन की समय सीमा साइट सौंपने की तारीख से 18 माह है (अर्थात् रेलवे साइडिंग के लिए अपेक्षित कुल भूमि 70%) है।

रेलवे साइडिंग परियोजनाओं की अनुमानित पूर्ति तारीख अक्टूबर, 2023 है (बशर्ते अप्रैल, 2022 तक साइट को सौंपा दिया गया हो)।

परियोजना का नाम	पूंजी लागत (करोड़ रुपए)	शुरू करने की प्रत्याशित समय-सीमा
(सीएचपी), साइलो आधारित प्रेषण और मशीनीकृत कन्वेयर प्रणाली	एमडीओ का दायरा 369.65 (लगभग)	अगस्त, 2023
रेलवे साइडिंग	294.87	अक्टूबर, 2023

6.2 भूमि अधिग्रहण:

➤ रेलवे साइडिंग के लिए भूमि की आवश्यकता निम्नानुसार है:

विवरण	काश्तकारी भूमि (एकड़)	सरकारी भूमि (एकड़)			कुल (एकड़)
		जलमंडार	गैर-वन	वन	
खान पट्टा सीमा से बाहर की भूमि	23.76	30.39	8.97	--	63.12
खान पट्टा सीमा से भीतर की भूमि	54.22	8.02	4.05	5.93	72.22
कुल	77.98	38.41	13.02	5.93	135.34

6.3 एमएल सीमा के बाहर की भूमि:

- i. **जलभंडार भूमि:** एनआईसीआईएल को मिट्टी तटबंध के स्थान पर पूर्ण/पुलिया के माध्यम से जलभंडार भूमि को क्रॉस करने की सलाह दी गई थी। रेलवे कॉरीडोर के लिए जलभंडार भूमि के उपयोग हेतु सशर्त प्रधान सचिव, डीओडब्ल्यूआर, ओडिशा सरकार से अनुमति प्रतिक्षित है।
- ii. **अन्य सरकारी भूमि:** सरकार की 2.1 एकड़ गैर-वनभूमि का अनुमोदन राजस्व बोर्ड, ओडिशा द्वारा किया गया है। एनएलसीआईएल को सरकारी भूमि स्थानांतरित करने के लिए डीसी, झारसुगुड़ा को आवेदन प्रस्तुत किया गया।
- iii. **काश्तकारी भूमि:** काश्तकार दिनांक 28.08.2020 को आयोजित डीसीएसी बैठक द्वारा दी गई दर से सहमत नहीं थे। इस मुद्दे का समाधान बढ़ी हुई भूमि दरों के तहत दिनांक 28.09.2021 को जिला प्रशासन द्वारा आयोजित बैठक के दौरान किया गया था। 1.9 एकड़ काश्तकारी भूमि का पंजीकरण पूरा हो गया है।

6.4 एमएल सीमा के भीतर भूमि:

- i. **जलभंडार भूमि:** एनआईसीआईएल को मिट्टी तटबंध के स्थान पर पूर्ण/पुलिया के माध्यम से जलभंडार भूमि को क्रॉस करने की सलाह दी गई थी। रेलवे कॉरीडोर के लिए जलभंडार भूमि के उपयोग हेतु सशर्त प्रधान सचिव, डीओडब्ल्यूआर, ओडिशा सरकार से अनुमति प्रतिक्षित है।
- ii. **काश्तकारी भूमि:** भूमि मुआवजे का वितरण किया जा रहा है।

6.5 पछवाड़ा साउथ ओसीपी (9 एमटीपीए):

- i. मैसर्स एनएलसी इंडिया लिमिटेड का जेवी नेयवेली,

उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) और मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) दुमका जिला, झारखंड में 9 एमटीपीए का पछवाड़ा साउथ कोयला ब्लॉक विकसित कर रहे हैं।

- ii. पछवाड़ा साउथ ओसीपी से कोयला उत्पादन वर्ष 2023-24 से आरंभ होने की संभावना है।
- iii. पछवाड़ा कोलफील्ड में, तीन कोयला ब्लॉक अर्थात् पछवाड़ा नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ हैं।
- iv. पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) और पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को क्रमशः निकटवर्ती पछवाड़ा नॉर्थ और पछवाड़ा सेंट्रल कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं।
- v. वर्तमान में, पछवाड़ा कोलफील्ड में कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है।
- vi. फर्स्ट माइल रोड कनेक्टिविटी को दूर करने के लिए कोयले के निष्कासन हेतु ईआर की पाकुर- हावड़ा लाइन पर लगभग 50 किलोमीटर (दक्षिण पाकुर) की दूरी पर इस कोयला ब्लॉक को नगरनबी स्टेशन से जोड़ना प्रस्तावित है।
- vii. कोयले के निष्कासन के लिए, झारखंड सरकार के सहयोग से रेल अवसंरचना के विकास हेतु मैसर्स एनयूपीपीएल और अन्य कोयला ब्लॉक आवंटितियों (मैसर्स डब्ल्यूबीपीडीसीएल और मैसर्स पीएसपीसीएल) तथा मैसर्स रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के बीच भागीदारी मॉडल आधारित एसपीवी का गठन किया जाना प्रस्तावित है।
- viii. मैसर्स आरआईटीईएस को परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया हुआ है।